

उच्च न्यायालय द्वारा पशु बलिपर प्रतर्बिंध का नरिणय

चर्चा में क्यों?

27 सतिंबर, 2019 को त्रपुरिा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदरिों में जानवरों और पक्षयिों की बलिदिने की परंपरा पर प्रतर्बिंध लगा दयिा। साथ ही न्यायालय ने सरकार को संबैधानकि मूलयों और सभी जानवरों एवं पक्षयिों के प्रतर्किरुणा, प्रेम, मानवता के महत्त्व के बारे में लोगों को जागरूक करने का नरिदेश दयिा।

ऐतहिासकि पृष्ठभूमि

- त्रपुरिा में पशु बलि की परंपरा कम-से-कम 500 वर्षों पुरानी है।
- पशु बलि मुख्य रूप से त्रपुरिा के दो मंदरिों - उदयपुर स्थति त्रपुरिश्वरी मंदरि और अगरतला के चतुरदश देवता मंदरि में होती है।
- दोनों मंदरिों की स्थापना त्रपुरिा पर शासन करने वाले माणकिय वंश के शासकों द्वारा की गई थी।
- त्रपुरिश्वरी मंदरि को 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ माना जाता है, जसकि स्थापना 1501 ईस्वी में महाराजा धन्य माणकिय ने की थी।
- चतुरदश देवता मंदरि को चौदह देवताओं का मंदरि कहा जाता है जसकि नरिमाण 1770 के आसपास महाराजा कृष्ण कशोर माणकिय द्वारा कराया गया था।
- पशु बलि की यह परंपरा त्रपुरिा में कम्युनसिट शासन के तहत भी जारी रही। हालाँकि अब तक केवल CPM ने इस आदेश का सार्वजनकि रूप से स्वागत कयिा है।
- त्रपुरिा संभवतः भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ राज्य सरकार 500 वर्ष से अधिक पुरानी दुर्गा पूजा को प्रायोजति करती रही है और जसकि पूर्ववर्ती शाही परिवार द्वारा प्रबंधन कयिा जाता है।
- लेकिन अब पूजा की तांत्रकि वधिपर प्रतर्बिंध से राज्य में बहस छडि गई है।

उच्च न्यायालय का पक्ष

- न्यायालय ने नरिणय दयिा कि जानवरों की बलिदिने की परंपरा को संबिधान के अनुच्छेद-25(1) के तहत संरक्षण ति नहीं कयिा जा सकता है। धार्मकि स्वतंत्रता सार्वजनकि व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थय के अधीन है।
- इसके अलावा पशु बलि अनुच्छेद-21 (जीवन का अधिकार) का उल्लंघन है।
- अदालत ने कहा कि धार्मकि परंपराएँ, पशु क्रूरता नवारिण अधनियम, 1960 के प्रावधानों की अवहेलना नहीं कर सकती।

सरकार का पक्ष

- सरकार ने तर्क दयिा कि त्रपुरिश्वरी और अन्य मंदरिों में पूजा पारंपरकि तरीके से जारी रहनी चाहयिे क्योंकि यह भारत में त्रपुरिा के वलिय के लयिे कयिे गए समझौते का भाग है।
- पूजा की तांत्रकि वधि के वरिुद्ध यह याचकिा इस्लाम धर्म में पशु बलि की परंपरा को शामिल नहीं करती है।
- अदालत ने इस तर्क को नरिथरक मानते हुए कहा कि कसिी बात की पुष्टि के लयिे आवश्यक सामग्री की अनुपस्थति में राज्य को इस तरह के स्टैंड लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
- उच्च न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिमि) द्वारा पशुबलि के मुद्दे को पहले ही मोहम्मद हनीफ कुरेशी और अन्य बनाम बिहार राज्य (1958), पश्चिमि बंगाल राज्य बनाम आशुतोष लाहडिी (1994) और मरिजापुर मोती कुरेशी कसाब बनाम गुजरात राज्य और अन्य (1998) जैसे मामलों में नपिटाया जा चुका है।
- इन मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दयिा था कि पशु बलि इस्लाम का एक अनवारि्य हसिा नहीं है और इसे धार्मकि स्वतंत्रता के आधार पर संरक्षण नहीं दयिा जा सकता है।
- इसमें यह भी कहा गया कि इस प्रथा पर प्रतर्बिंध लगाने के लयिे कानून बनाने हेतु राज्य स्वतंत्र है। हालाँकि एक सामान्य प्रतर्बिंध के प्रश्न पर अदालतों की अलग-अलग राय है।
- त्रपुरिा के शाही परिवार के वंशज प्रद्योत कशोर माणकिय देववर्मन और राज्य सरकार ने भी इस नरिणय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने की बात कही है।

स्रोत : द इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/high-court-decides-to-ban-animal-sacrifice>

